भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 868

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2026 को दिया जाना है ।

17 माघ, 1947 (शक)

इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण पर पीएलआई योजना का प्रभाव

868. श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े:
श्री मयंककुमार नायक:
श्रीमती किरण चौधरी:
श्रीमती संगीता यादव:
श्रीमती रेखा शर्मा:
श्री दीपक प्रकाश:
श्रीमती दर्शना सिंह:
श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई:
डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी
श्री रायगा कृष्णैया:
श्री लहर सिंह सिरोया:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं की शुरूआत के बाद से घरेलू इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण उत्पादन और निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है, वर्ष-वार बजट आवंटन और राज्य-वार आंकड़े क्या है;
(ख) मंत्रालय द्वारा समर्थित पहलों का आयात पर निर्भरता कम करने, रोजगार सृजन करने और मोबाइल विनिर्माण, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी और हार्डवेयर घटकों जैसे क्षेत्रों को सुदृढ़ करने में राज्य-वार क्या प्रभाव पड़ा है;
(ग) राज्य-वार भागीदारी और लाभों सहित भारतीय एमएसएमई और स्टार्टअप्स को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिकी मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने में सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) क्या सरकार भारत के इलेक्ट्रॉनिकी पारितंत्र को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर या सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) जैसे नए उपायों पर विचार कर रही है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): माननीय प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए कई नीतिगत पहल की हैं। जिसके परिणामस्वरूप, पिछले 11 वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में काफी विस्तार हुआ है, जिसे निम्नलिखित आंकड़ों से देखा जा सकता है:

#	2014-15	2024-25	टिप्पणियां
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का उत्पादन (रु.)	~1.9 लाख करोड़	~11.3 लाख करोड़	6 गुना वृद्धि
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का निर्यात (रु.)	~0.38 लाख करोड़	~3.3 लाख करोड़	8 गुना वृद्धि
मोबाइल फोनों का उत्पादन (रु.)	~0.18 लाख करोड़	~5.5 लाख करोड़	28 गुना वृद्धि
मोबाइल फोनों का निर्यात (रु.)	~0.01 लाख करोड़	~ 2 लाख करोड़	127 गुना वृद्धि

भारत सरकार ने देश में मोबाइल फोन के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 2020 में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (एलएसईएम) के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की। मोबाइल फोन का उत्पादन वित्त वर्ष 2019-20 में 2.14 लाख करोड़ रुपये से दोगुने से अधिक बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 5.5 लाख करोड़ रुपये हो गया है।परिणामस्वरूप, भारत दुनिया में दूसरे सबसे बड़े मोबाइल निर्माता के रूप में उभरा है। मोबाइल फोन का निर्यात वित्त वर्ष 2019-20 में 0.27 लाख करोड़ रुपये से ~8 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये हो गया है। भारत 2014 में मोबाइल फोन का आयातक होने से मोबाइल फोन का शुद्ध निर्यातक बन गया है। दिसंबर 2025 तक, इस योजना ने 15,172 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है और 1,71,448 व्यक्तियों का अतिरिक्त रोजगार सृजन किया है।

इसके बाद, भारत सरकार ने आईटी हार्डवेयर (लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर, आदि) के लिए एक सुदृढ़ घरेलू विनिर्माण इकोसिस्टम बनाने, बड़े निवेश को आकर्षित करने, आयात निर्भरता को कम करने और भारत को एक विश्वसनीय वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला केंद्र बनाने के लिए 2023 में आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई 2.0 भी लॉन्च किया है। दिसंबर 2025 तक, योजनाओं ने कुल संचयी उत्पादन 16,531 करोड़ रुपये का किया है, कुल संचयी निवेश 856.64 करोड़ रुपये और कुल संचयी रोजगार 4,776 (प्रत्यक्ष नौकरियां) हुआ है।

आयात निर्भरता को कम करने और रोजगार सृजित करने हेतु, सरकार ने पिछले 11 वर्षों में मोबाइल फोन विनिर्माण, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार आदि का समर्थन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिनमें शामिल हैं:

- इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना (एसपीईसीएस)
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी और ईएमसी 2.0) योजना
- सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम
- सार्वजनिक खरीद में घरेलू स्तर पर निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017
- टैरिफ तंत्र को युक्तिसंगत बनाने, पूंजीगत वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क में छूट आदि सहित कराधान में सुधार किए गए हैं।
- लागू कानूनों/विनियमों के अधीन इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस)

हाल ही में शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस) का उद्देश्य मूल्य श्रृंखला में निवेश (वैश्विक/घरेलू) को आकर्षित करके सुदृढ़ घटक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। इस योजना को अब तक उद्योग से अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली है।59,350 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश की तुलना में 1.15 लाख करोड़ रुपये के निवेश मूल्य वाली परियोजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की योजनाएं घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एमएसएमई एकीकरण को प्रोत्साहित करती हैं। एलएसईएम के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत, 32 लाभार्थियों में से 14 एमएसएमई श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह, आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत, 27 लाभार्थियों में से 8 एमएसएमई हैं। इसके अलावा, कई एमएसएमई ने स्पेक्स और ईसीएमएस योजनाओं में भाग लिया है।

सेमीकंडक्टर डिजाइन भाग पर, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) योजना के अंतर्गत अनुमोदित सभी 24 परियोजनाएं घरेलू एमएसएमई/स्टार्टअप की हैं।

भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम/पहल अखिल भारतीय स्तर पर लागू हैं और किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कोई भी कंपनी, जिसमें लघु एवं मध्यम उद्यम और स्टार्टअप शामिल हैं, इन कदमों/पहल के अंतर्गत लाभ उठा सकती है।

देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी डोमेन के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, एमईआईटीवाई ने निम्नलिखित पहल की हैं:

- **टाइड 2.0 (टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स) योजना:** एमईआईटीवाई ने इनक्यूबेटरों को वित्तीय और तकनीकी सहायता के माध्यम से प्रौद्योगिकी-आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2019 में टाइड 2.0 योजना शुरू की है। यह योजना लगभग 2000 तकनीकी स्टार्टअप को संभालने के लिए 5 वर्षों की अवधि में पूरे भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों और प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठनों में 51 चयनित इन्क्यूबेटरों के माध्यम से स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान कर रही है।
- **जेनेसिस (इनोवेटिव स्टार्टअप्स के लिए जेन-नेक्स्ट सपोर्ट) योजना:** एमईआईटीवाई ने पांच वर्षों की अवधि में पूरे भारत में टियर- II और टियर- III शहरों में स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 'जेन-नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स (जेनेसिस)' योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य लगभग 1,600 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, उनको पोषित करना और उन्हें विकसित करना है।

******